दूरभाष– 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांक: 4977 /993/दो/2017

दिनांक: 19/1/17

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण।

विषयः–**प्रदेश में राज्य मुकदमा नीति लागू होने पर मा0 उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वादों की कमी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–4117/नौ–4–16–29ज/15 दिनांक 04.01.2017 एवं उसके साथ संलग्न विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–572/सात–न्या0अनु0प्रको0/2016–01/न्याय–अनु.प्र.को./2015 दिनांक 19.12.2016 की संलग्नकों (भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.06.2014 व निर्धारित प्रारूप) सहित छायाप्रति प्रेषित करते हुए कृपया उक्त वादों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) के पत्र संख्या–572/सात–न्या0अनु0प्रको0/2016–01/न्याय–अनु.प्र.को./2015 दिनांक 19.12.2016 से संलग्न भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.06.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त वादों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना अभिकरण को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) को सूचना समयान्तर्गत प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–प्रारूप की प्रति।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–28/69–1–2017–12(रिट)/2012 दिनांक 10.01.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

Proforma for Assessment of Impact of Implementation of State Litigation Policy

Name of the State: _____

1. Reduction of Pendency of Cases in High Court in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).

Sr. No.	Particulars	Number of Cases pending in High Court as on 01.07.2014 in which State Government was a party	Number of Cases in which State Government was party added during 01.07.2014 to 31.12.2014.	Number of cases disposed aby High Court from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of Cases pending in High Court as on 31.12.2014 in which State Government was party	Remark if any*
1.	Pending cases 0 to 1 year old						
2.	Pending cases 1 to 5 years old						
3.	Pending cases more than 5 years old						
Total							

2. Reduction of Pendency of Cases in Subordinate Courts in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).

Sr. No.	Particulars	Number of Cases pending in Subordinate Courts as on 01.07.2014 in which State Government was a party	Number of Cases in which State Government was party added during 01.07.2014 to 31.12.2014.	Number of cases disposed aby Subordinate Courts from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of Cases pending in Subordinate Courts as on 31.12.2014 in which State Government was party	Remark if any*
1.	Pending cases 0 to 1 year old						
2.	Pending cases 1 to 5 years old						
3.	Pending cases more than 5 years old						
Total							

"In case it has not been possible to reduce pendency of Cases in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant), the reasons, if any, for the same could be mentioned under remarks column."

3. Special Measures, if any, taken by the State Government for reduction in pendency of Cases in which State Government, was a party (petitioner or respondent or appellant).

****